

साथिक आदेश दिनांक..... 07/1/18
की पालना में पत्र नीचे वाले..... 09/11/1987 5504 0211
दिनांक 11/3/23 को पत्र हो


उपस्थ अधिकारी
कठमार (अलवर)

11/3/23

कठुवाण उपखण्ड 09/11/1987 5504 0211
पत्र लिखा गया था कि वहाँ की वहाँ की
वहाँ की वहाँ की 11/3/23 को पत्र की
होकर

17/3/23

कठुवाण उपखण्ड अना प्रान्त का प्रान्तों पत्र
09/11/1987 साहित्य होने से कठुवाण प्रान्त
पाया जाता है अना प्रान्त का प्रान्त 09/11/1987
साहित्य होने से कठुवाण वहाँ की वहाँ की
रुद्ध पत्र खातिर प्रान्तों प्रान्तों है
विशेष प्रान्तों के निम्नान्त प्रान्तों प्रान्तों
प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों
प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों
प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों प्रान्तों


उपस्थ अधिकारी
कठुमार (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कतूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी- लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

प्रकरण संख्या 1/150/2011

मीरा कुमारी वगैरा बनाम भुजमल वगैरा

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

उपस्थित-

श्री तेजसिंह राठी एडवोकेट-अधिवक्ता वादीगण

श्री धनश्याम शर्मा एडवोकेट- अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1-2

आदेश दिनांक 17-07-23

प्रतिवादी सं0 2 शिवप्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादी सं0 4 सरपंच ग्राम पंचायत रेटा के विरुद्ध दावा पेश किया है कानूनन पंचायत राज्य के कर्मचारी के प्रतिनिधि के विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत मियादी 2 माह का नोटिस दिया जाना जरूरी है लेकिन वादीगण ने विना नोटिस दिये ही प्रतिवादी संख्या 4 सरपंच ग्राम पंचायत रेटा के विरुद्ध दावा पेश किया है जिस कारण वादीगण का दावा विना नोटिस प्रेषित किये ही पेश करने के दावा अदालत श्रीमान में मेण्टनेविल ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है जो इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र की नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण ने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के विरुद्ध ही-रिलीफ चाही है। ग्राम पंचायत के विरुद्ध वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहा है। ग्राम पंचायत रेटा दावा में फोरमल पार्टी है जिस कारण धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। जिस कारण वाद वादीगण घोषणात्मक चलने योग्य है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कतूमर (अलवर) राज0

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 2 ने अपनी बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादीगण ने ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया है कानूनन दावा पेश करने से पूर्व वादीगण को धारा 109 पंचायत राज अधिनियम का नोटिस देना जरूरी था जो वादीगण द्वारा नहीं दिया गया है इस वजह से वाद वादीगण कानून से बाधित होने से वाद वादीगण खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अधिवक्ता वादीगण के कथनों का बहस करते हुये अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध ही अनुतोष चाहा है ग्राम पंचायत फोरमल पार्टी है इस वजह से ग्राम पंचायत को धारा 109 जा०दी० का नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र वादीगण के जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

आर्डर 7 रूल 11 जा०दी० का प्रार्थना पत्र निम्न तीन विन्दुओं पर पर तय किया जावेगा।

1. जहां वाद-हेतुक (Cause of Action) प्रकट नहीं करता हो।
2. जहां वाद उचित कोर्ट फीस (Court Fee) प्रकट नहीं करता हो।
3. जहां वाद विधि से बर्जित हो।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थना में पक्षकारान के मध्य वाद हेतुक व कोर्ट फीस के विन्दु पर कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी सं० 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादीगण ने ग्राम पंचायत को दावा हाजा में प्रतिवादी सं० 4 अंकित किया है कानूनन वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व ग्राम पंचायत को धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत 2 माह का कानूनी नोटिस देना चाहिए था। मियाद गुजरने के बाद दावा पेश करना चाहिए था इस वजह से वाद वादीगण विधि से बर्जित है। विद्वान अधिवक्ता का कथन कि ग्राम पंचायत फोरमल पार्टी है जिसे धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत कानूनी नोटिस देना जरूरी नहीं है। हमने वाद पत्र के टाइटल का अवलोकन किया जिसमें वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत को असल प्रतिवादीगण के रूप में प्रतिवादी सं० 4 अंकित किया हुआ है जबकि अन्य सहखातेदारान को तरतीवी

प्रतिवादीगण (फोरमल पक्षकार) दर्ज किया है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि ग्राम पंचायत दावा हाजा में फोरमल पार्टी हो। अधिवक्ता प्रतिवादी ने इस तथ्य की पुष्टि में कानूनी नजीर पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 पेश की जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायती राज संस्था के विरुद्ध या उसके किसी भी सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध या किसी पंचायती राज संस्था या-उसके किसी भी सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन कोई वाद पेश करने से पूर्व दो माह का लिखित नोटिस दिया जाना अनिवार्य (Mandatory) है और नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद ही वाद पेश किया जावेगा तथा कानूनी नजीर आर एल डब्ल्यू 1998 (1) पेज 555 मेवाराम बनाम राजस्थान सरकार में भी स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम पंचायत के विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व 2 माह के नोटिस दिये जाने की पालना किया जाना आवश्यक (Necessary) है। जबकि वादीगण ने दावा के जिमन नं० 7 में यह साफ अंकित किया है कि "तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी के सहखातेदार काश्तकार है जो दावा हाजा की तकमील में आवश्यक पक्षकार होने के कारण तरतीवी प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाये है जिनके खिलाफ वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते।" इससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत रेटा से वादीगण रिलीफ चाहते है इस वजह से ग्राम पंचायत को असल प्रतिवादी अंकित किया है। पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत के विरुद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 109 पंचायत राज अधिनियम की कानूनी पालना नहीं की गयी है इस वजह से वाद वादीगण विधि से वर्जित है। अतः प्रतिवादी सं० 2 शिवप्रकाश का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा०दी० स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण वाद संख्या 1/150/2011 खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैंसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 17-07-23 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
कतूमर (अलवर)